

62

न्यायालय श्रीमान् स्वस्य महोदय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर  
रीवा सर्किट कोर्ट रीवाम०प्र०

161  
5.4.13

निगरानी प्रकरण क्र० / 2013

R-1719-III/13



श्री स्वयंनारायण वरमा तनय बीरमान वरमा उम्री 40 वर्ष, पेशा  
खेती, निवासी ग्राम पलिया 350 तहो मगवां, जिलारीवाम०प्र०  
दत्ता पेशा 5.4.13  
मलक बाफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल, म०प्र०  
ग्वालियर

श्री स्वयंनारायण वरमा तनय बीरमान वरमा उम्री 40 वर्ष, पेशा  
खेती, निवासी ग्राम पलिया 350 तहो मगवां, जिलारीवाम०प्र०

आवेदक

वनाम

श्री रामप्रसाद वरमा तनय भारतप्रसाद वरमा उम्री 58 वर्ष, सा० पलिया  
350 तहो मगवां, जिलारीवाम०प्र०

आवेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार मगवां  
जिलारीवादिनांक 12-3-13 बावत प्रकरण क्र०  
31अ12/2010-11

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मूराजस्व संहिता सन 1959 ई०

प्रकरण के सन्धिपत मे तथ्य

ग्राम पलिया तहो मगवां रीवा की भूमि न० 3/1क, 4/4, 6/3,  
8/4, 9/4 जो आवेदक के स्वत्व व आपिपत्य की भूमि हैं, कैंतमीम  
व सीमांकन का मामला आवेदक ने तहसीलदार मगवां से वायर किया  
जिसका विधिवतजांच कर तमीम प्रस्ताव तारीख 9-7-10 को दिया  
गया और तमीम व सीमांकनकी प्राथी को विलंबित करने के उद्देश्य

श्री रामप्रसाद वरमा  
10/10/2013

स्वयंनारायण वरमा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक 1719-तीन/2012 निगरानी

जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/7/18	<p>उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये । उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मनगवां जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 31 अ-12/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 12-3-13 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>२/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं तहसीलदार, तहसील मनगवां जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 31 अ-12/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 12-3-13 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार का यह आदेश अंतिम स्वरूप का है क्योंकि तहसीलदार ने यह आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 70 के अंतर्गत नक्शा तरमीम कार्यवाही पर पारित किया है, जिसके विरुद्ध प्रथम अपील उपखंड अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) को प्रस्तुत होगी।</p> <p>म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को-आपरेटिव सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरुद्ध बल्लुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सबसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।</p> <p>आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि ऐसी कौनसी विषम परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनी जावे।</p>	

प्र0क0 1719-तीन/2012 निगरानी

आवेदक को इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विधि के प्रावधानों के अनुसरण में अपील प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है। विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में सीधे सुनवाई योग्य न होने से गुणदोष पर विचार किये बिना इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

  
सदस्य

M